

मामलों का विवरण

रैम एलएल

वी.

राजस्थान और ओआरएस का राज्य। (2023 की सिविल अपील संख्या 7935) 4 दिसंबर, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या विभागीय जांच के अनुसार अपीलार्थी-सिपाही को सेवा से बर्खास्त करना न्यायोचित था और विभागीय जांच में पारित बर्खास्तगी के आदेश पर आपराधिक मुकदमे में अपीलीय न्यायाधीश द्वारा आदेशित बरी करने का क्या प्रभाव है।

सेवा कानून-धोखाधड़ी के आरोप पर विभागीय जांच के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी-न्यायसंगत आरोप-आपराधिक मुकदमे में अपीलीय न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने का आदेश, बर्खास्तगी के आदेश पर-अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-पद पर भर्ती के समय खुद को बहुमत प्राप्त करने के रूप में पेश करने के लिए अपनी 8 वीं कक्षा की अंकपत्र में अपनी जन्म तिथि में बदलाव करना-विभागीय कार्यवाही की शुरुआत-सेवा से बर्खास्तगी-अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना-दोषसिद्धि और सजा। **420** हालाँकि, निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी., अपीलीय अदालत द्वारा बरी किया गया-बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने और सेवा में फिर से स्थापित करने की मांग करने वाली लिखित याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई-सच्चाई:

आयोजित किया गया: अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान, आरोप पत्र में संलग्न अपीलार्थी की 8 वीं कक्षा की अंकपत्रिका और मूल अंकपत्र, जिसका आरोप पर सीधा असर होता है, के प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके आरोपों के प्रमाण के बारे में निष्कर्ष निकाला गया-

अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने केवल जांच रिपोर्ट में तर्क को दोहराया-अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि आवेदन पत्र में पुनर्लेखन केवल एक अनजाने में हुई त्रुटि के सुधार के कारण था, जब तक कि मूल 8 वीं कक्षा 809 स्वीकार किया जाता है।

808

राम लाल बनाम राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस.

मार्कशीट में उसकी जन्म तिथि को 21.04.1972 के रूप में दर्शाया गया है और उस दस्तावेज़ में कोई सुधार या हेरफेर नहीं है, अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, पूरे फैसले को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद बरी कर दिया गया था और यह देखने के बाद कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा-आपराधिक मामले में अपीलीय न्यायाधीश के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप न्यायसंगत नहीं था, साबित नहीं हुआ था,

वास्तव में आरोप भी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा "अस्वीकृत" था-आरोप केवल समान नहीं थे बल्कि सबूत, गवाह और परिस्थितियाँ समान थीं-इस प्रकार, समाप्ति का आदेश, अपीलिय प्राधिकरण का आदेश, पुनर्विचार करने से इनकार करने के आदेश और पुनर्विचार करने के आदेश।

न्यायिक समीक्षा-अनुशासनात्मक प्राधिकरण का आदेश-रिट अदालत की समीक्षा करने की शक्ति:

आयोजित किया गया:बहुत सीमित है-जांच का दायरा केवल यह जांचने के लिए है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया वैध है-अदालतों को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की है और यदि ऐसा है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं-केवल एक आपराधिक अदालत द्वारा बरी होने से कर्मचारी को किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसमें बहाली भी शामिल है-हालाँकि, यदि विभागीय जांच और आपराधिक अदालत में आरोप समान या समान हैं, और यदि सबूत, गवाह और परिस्थितियाँ एक ही हैं, तो मामला एक अलग आयाम प्राप्त करता है-अदालत को अपने विवेक का प्रयोग करने और राहत देने का अधिकार होगा, अगर वह यह निष्कर्ष निकालती है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को खड़े होने देना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा।[पैरा 11-13]

शब्द और वाक्यांश-अभिव्यक्तियाँ "संदेह का लाभ" और "सम्मानपूर्वक बरी", निर्णयों में उपयोग किए जाते हैं-प्रभाव:

आयोजित किया गया:उक्त अभिव्यक्तियों को जादू के मंत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए-कानून का न्यायालय केवल इस तरह की शब्दावली के उपयोग से प्रभावित नहीं होगा-न्यायिक समीक्षा में न्यायालय जांच करने के लिए बाध्य है।

810

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

निर्णय का सार और उपयोग की गई अभिव्यक्ति के रूप में नहीं जाता है।[पैरा 25]

साक्ष्य अधिनियम, **1872**-तथ्य, जब इसे 'अस्वीकृत' कहा जाता है:

आयोजित किया गया:एक तथ्य को "अस्वीकृत" कहा जाता है जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, अदालत या तो यह मानती है कि इसका अस्तित्व नहीं है या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानती है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है-तथ्य को "साबित नहीं" कहा जाता है जब यह न तो "साबित" होता है और न ही "अस्वीकृत" होता है।[पैरा 26]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जी. एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2006) 5 एस. सी. सी. 446 -

पर भरोसा किया।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम ए. जी. डी. रेड्डी 2023:आई. एन. एस. सी:766 = 2023 (11) स्केल 530; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम विश्वनाथ भट्टाचार्य

2022:आई. एन. एस. सी:117 = (2022) 13 एस. सी. सी. 329; उप महानिरीक्षक

पुलिस और एक अन्य बनाम एस. समुथिरम (2013) 1 एस. सी. सी. 598; स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम पी. काटा राव, (2008) 15 एस. सी. सी. 657; विजय सिंह और

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 3 एस. सी. सी. 190-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 7935।

2011 के एस. ए. No.484 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2018 से।

रूप:

आदर्श प्रियदर्शी, अभिजीत सिन्हा, सार्थक गौरव, सुश्री रिम्मी भारद्वाज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विशाल मेघवाल, श्रीमती पद्मलक्ष्मी अयंगर, सुश्री नेहा कपूर, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए।

811

राम लाल बनाम राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस.

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश के. वी. विश्वनाथन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. राम लाल (अपीलार्थी) राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी, 9 वीं बटालियन, जोधपुर के साथ एक सिपाही थे।उन्हें 15.12.1991 पर नियुक्त किया गया था।उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,467,468 और 471 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी। इसके तुरंत बाद, 02.04.2003 पर, विभागीय जांच में एक आरोप पत्र भी जारी किया गया था।3. दोनों

कार्यवाहियों में एक ही आरोप था कि अपीलार्थी ने अपनी 8 वीं कक्षा की अंकपत्रिका में अपनी जन्म तिथि को 21.04.1974 से 21.04.1972 में बदल दिया। यह आरोप लगाया गया था कि भर्ती के समय खुद को बहुमत प्राप्त करने के रूप में पेश करने के लिए ऐसा किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया।

4. आवेदन में अधिलेखन के बारे में पूछे जाने पर, अपीलार्थी ने कहा कि यह संभव है कि आवेदन पत्र में उन्होंने शुरू में 21.04.1974 लिखा हो और उसके बाद इसे 21.04.1972 में सही किया हो। हालाँकि उन्होंने कहा कि उनकी जन्म तिथि 21.04.1972 थी।

5. विभागीय कार्यवाही में पाँच गवाहों से पूछताछ की गई। आपराधिक मुकदमे में आठ अन्य गवाहों के अलावा इन गवाहों से भी पूछताछ की गई थी, जिनसे आपराधिक मुकदमे में भी पूछताछ की गई थी। विभागीय कार्यवाही में पूछताछ कार्यालय ने आरोपों को साबित पाया और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 31.03.2004 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलीय प्राधिकरण ने भी अपील को खारिज कर दिया। आदेश की समीक्षा करने और जुर्माने पर पुनर्विचार करने के प्रयास भी व्यर्थ रहे।

6. आपराधिक मुकदमे में, निचली अदालत ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। हालाँकि, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, जोधपुर [‘अपीलीय न्यायाधीश’] ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को बरी कर दिया।

812

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

7. इसके बाद, अपीलार्थी ने अपनी बहाली के लिए प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद, उन्होंने अगस्त, 2008 में अपीलीय प्राधिकरण के दिनांकित बर्खास्तगी आदेश, और उपरोक्त आदेशों की समीक्षा और पुनर्विचार करने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका का नेतृत्व किया। 8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक अलग-अलग है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश में कोई असंवेदनशीलता नहीं पाई। अपीलार्थी के नेतृत्व में रिट अपील को भी विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों को दोहराते हुए और यह स्पष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया है कि विभागीय कार्यवाही में किसी आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा के मानदंड कैसे सीमित और सीमित हैं। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी हमारे समक्ष अपील में है।

विचार के लिए प्रश्न:

9. विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं:

क) क्या विभागीय जांच के अनुसार अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना न्यायोचित था?

ख) मामले के तथ्यों पर, विभागीय जांच में पारित बर्खास्तगी के आदेश पर, आपराधिक मुकदमे में अपीलीय न्यायाधीश द्वारा आदेशित बरी करने का क्या प्रभाव है?

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री आदर्श प्रियदर्शी और राज्य के विद्वान वकील श्री विशाल मेघवाल को सुना है। विद्वान वकीलों ने नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष अपनी दलीलें दोहराई हैं।

कानूनी स्थिति:

11. हमने दोनों प्रश्नों की स्वतंत्र रूप से जांच की है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश की समीक्षा करने की रिट अदालत की शक्ति बहुत सीमित है। जाँच का दायरा केवल यह जाँचने के लिए है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया वैध है या नहीं। [भारतीय स्टेट बैंक बनाम देखें। ए. जी. डी रेड्डी, 2023:आई. एन. एस. सी:766 = 2023 (11) स्केल 530]। उस अभ्यास के हिस्से के रूप में, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेशों ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की है और यदि ऐसा है, तो अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं।

[यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम विश्वनाथ भट्टाचार्य, 2022 देखें। आई. एन. एस. सी:117 = (2022) 13 एससीसी 329] 813

राम लाल वी. स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ओआरएस।

12. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि आपराधिक अदालत द्वारा केवल बरी किए जाने से कर्मचारी को किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसमें शामिल हैं -

पुनर्स्थापना। (पुलिस उप महानिरीक्षक और एक अन्य बनाम एस. समुथिरम, (2013) 1 एस. सी. सी. 598 देखें।

13. तथापि, यदि विभागीय जांच और आपराधिक न्यायालय में आरोप समान या समान हैं, और यदि साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियाँ एक ही हैं, तो मामला एक अलग आयाम प्राप्त करता है। यदि न्यायालय न्यायिक समीक्षा में यह निष्कर्ष निकालता है कि आपराधिक कार्यवाही में बरी होना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद था और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा में कुछ परिस्थितियों में निवारण प्रदान कर सकता है। न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने और राहत देने का हकदार होगा, यदि वह यह निष्कर्ष निकालता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषों को खड़ा होने देना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर बदल जाएगा। [जी. एम. टैंक बनाम देखें।

गुजरात राज्य और अन्य, (2006) 5 एस. सी. सी. 446, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

बनाम पी. काटा राव, (2008) 15 एस. सी. सी. 657 और एस. समुथिरम (ऊपर)]

चर्चा:

अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता-प्रश्न संख्या 1:

14. मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विश्लेषण आवश्यक है। इस विवाद की उत्पत्ति, जो विश्वास को बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करती है, इस प्रकार है। अपीलार्थी के चचेरे भाई श्रवण लाल (विभागीय जांच में पीडब्लू-4 और आपराधिक मामले में पीडब्लू-6) को आधिकारिक तौर पर जांच से पहले इस प्रकार बयान दिया गया:- “पूछताछ में बताया गया कि लगभग 13 महीने पहले, मैं वेल में इंजन चला रहा था। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे रामलाल शराब पीकर कुएँ पर आया और इंजन बंद कर दिया। इसके बाद, रामलाल ने मुझे गाली दी और मेरे साथ हाथापाई की और कहा कि आज मैं इंजन चलाऊंगा और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे सरकार को मूर्ख बनाकर नौकरी मिली है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो रामलाल ने मुझे बताया कि मुझे अपनी मार्कशीट में अपनी जन्म तिथि को 21.04.1972 के रूप में बदलकर नौकरी मिली है, जबकि मेरी जन्म तिथि 21.04.1974 थी। इसके बाद मैं स्कूल गया और इस तथ्य के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद मुझे पता चला कि उनकी जन्म तिथि 21.04.1974 थी। इस कारण से, मैंने पुलिस अधीक्षक, अजमेर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और कमांडेंट, 9 वीं बटालियन, 814 को एक रिपोर्ट दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आर. ए. सी., टोंक और मैंने भी एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को और एक रिपोर्ट डी. आई. जी., आर. ए. सी., राजस्थान, जयपुर को दी।

02.09.2002 पर एक एफ. आई. आर. पंजीकृत किया गया था। विभागीय कार्यवाही में एक आरोप पत्र 02.04.2003 पर जारी किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में दो आरोपों को निकालना प्रासंगिक होगा:

“शुल्क संख्या 1:-

वर्ष 1991 में, आपके द्वारा कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया गया था, जिसके साथ, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तिलोनिया (अजमेर) द्वारा जारी 8 वीं पास की मार्कशीट, जिसमें अनुक्रमांक 323 और प्रवेश संख्या 2314 है, जिसमें आपकी जन्म तिथि का उल्लेख 21.04.1974 के रूप में किया गया था, लेकिन आप इसे 21.04.1972 में बदलकर, धोखाधड़ी से कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गए।

शुल्क संख्या 2:-

सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तिलोनीया (अजमेर) द्वारा जारी मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि को 21.04.1974 से 21.04.1972 में बदलने के परिणामस्वरूप, पी. एस. मंडोर, जिला-जोधपुर में

आपके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध संख्या 183/02 दर्ज की गई थी।”

15. विभागीय जाँच में पाँच गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें पीडब्लू-1 जगदीश चंद, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, गाँव तिलोनिया के प्राचार्य, पीडब्लू-2 भवानी सिंह (सिपाही जिसे स्कूल के रिकॉर्ड लाने का काम सौंपा गया था), पीडब्लू-3 करण शर्मा, जो सर्कल ऑफिसर थे और जिन्होंने श्रवण लाल का बयान दर्ज किया था; पीडब्लू-4 श्रवण लाल और पीडब्लू-5 राज सिंह जिन्होंने अपराधिक मामले की जाँच की थी।

16. पीडब्लू-5/राज सिंह का साक्ष्य, जैसा कि जांच रिपोर्ट में दिया गया है, महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप को गलत साबित किया है। जाँच अधिकारी के समक्ष जिरह में उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं:

“राज सिंह आपने अपराध संख्या 102 की जांच की और इसकी प्रति कमांडेंट, 9 वीं बटालियन, आर. ए. सी., टोंक को भेजी, आपने इसके साथ कौन से दस्तावेज भेजे-जो दस्तावेज मेरे द्वारा भेजे गए थे, वे एफ. आई. आर. की प्रति, आरोप पत्र की प्रति थी जो अदालत में प्रस्तुत की गई थी और जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान और दस्तावेज थे। जिनकी फोटोकॉपी भी अभियुक्तों को दी गई थी। क्या आपने उपरोक्त मामले में दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां 815 पर भेजी थीं

राम लाल वी. स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ओआरएस।

कमांडेंट-मैंने प्रतियां कमांडेंट साहब को नहीं भेजी थीं। किस अधिकारी ने अदालत में आरोप पत्र, परिणाम का आदेश प्रस्तुत किया था-पी. एस. मंडोर, जिला-जोधपुर शहर के तत्कालीन एस. एच. ओ. अर्थात् श्री। राम प्रताप ने अदालत में आरोपी के खिलाफ जांच, आदेश और आरोप पत्र का परिणाम प्रस्तुत किया।”

जाँच के दौरान, आपने धर्मेन्द्र कुमार जाटव और जयराम गुर्जर के बयान दर्ज किए थे, क्या आपने और बयान दर्ज किए थे और क्या आप उन बयानों की प्रतियों की पहचान करेंगे-हाँ, मैंने गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। और मैं इसके साथ दोनों उपरोक्त गवाहों के बयान प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या वे स्वयं लिखे गए हैं-हाँ, वे कथन मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो एक्सएच हैं। डी-1 और एक्सएच। डी-2। एक्सएच में। डी-1, मैंने ए से बी भाग पर रकिशन देव मुरारी नामक शिक्षक का बयान दर्ज किया और मैंने रामलाल की अंकपत्रिका भरी, जिसमें रामलाल की जन्म तिथि सी से डी भाग में 21.04.1972 के रूप में उल्लिखित है, जिसे चेकिंग टीचर रामकिशन देव मुरारी के निर्देश के अनुसार लिखा गया है। ई से एफ भाग पर उल्लिखित 21.07.1972 की जन्म तिथि का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया था, वास्तव में, यह मानवीय त्रुटि के कारण लिखा गया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं-यह कथन सही है, जबकि, पुलिस आरएसी में भर्ती के लिए फॉर्म भरने के समय, रामलाल 9 वीं पास की टी. सी. संलग्न कर सकते थे, और वह 10 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे।”

इसके बाद, एक्सएच का जिक्र करते हुए। डी-2 [जयराम गुर्जर का बयान], उन्होंने निम्नानुसार अपदस्थ किया:-

“इसी तरह, एक्सएच में। डी-2, ए से बी भाग पर, आपने मुझे रामलाल एस/ओ एस की 8 वीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी दिखाई है। तेजुराम चौधरी, आर/ओ तिलोनीया, जिस पर इसके जारीकर्ता यानी शिक्षक श्री के हस्ताक्षर हैं। धर्मेन्द्र कुमार, रामकिशन देव मुरारी और प्रधानाध्यापक एस. विष्णु मियानी का उल्लेख किया गया है। मैं उनके हस्ताक्षरों से परिचित हूँ।”

17. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी की 8 वीं कक्षा की मार्कशीट, जो कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाले उनके आवेदन का आधार थी, के बारे में पीडब्ल्यू-5/राज सिंह ने नीचे कहा है:-

816

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“रामलाल की 8 वीं कक्षा की मार्कशीट दस्तावेजों में संलग्न है, जो एक्सएच है। पी-3, (एस. आई. सी.) जिसमें, कहीं भी जन्म तिथि में कोई परिवर्तन पाया गया है, और क्या उसमें जन्म तिथि का उल्लेख 21.04.1972 के रूप में किया गया है-हां, 8 वीं कक्षा की अंकपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और जन्म तिथि 21.04.1972 है।”

18. उपरोक्त से यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थी की 8 वीं कक्षा की अंकपत्रिका (जो कमांडेंट को भेजे गए संलग्न दस्तावेजों का हिस्सा है) में कोई बदलाव नहीं पाया गया था और उस पर उल्लिखित जन्म तिथि 21.04.1972 थी। उपरोक्त उद्धरण में 'पी-3' का संदर्भ एक गलती प्रतीत होती है। आरोप पत्र और संलग्न दस्तावेज पूर्व थे। पी-12/1 से पी-12/1 2। डिफेंस ने 8 वीं कक्षा की मूल अंकपत्रिका को भी अलग से एक्सएच के रूप में प्रदर्शित किया। डी-3, जैसा कि जांच रिपोर्ट में दिए गए प्रदर्शनों के चार्ट से स्पष्ट है। 19. पूछताछ कार्यालय ने गवाहों के बयानों को निर्धारित करने के बाद, "पी" श्रृंखला के प्रदर्शनों और अपराधी के प्रदर्शनों, अर्थात् "डी" श्रृंखला के चार्ट को निर्धारित किया, और आरोप-1 के संबंध में निम्नलिखित को दर्ज किए गए साक्ष्य की आगे की चर्चा या मार्शलिंग के बिना: “पी. डब्ल्यू.-1 पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-3, पी. डब्ल्यू.-4, पी. डब्ल्यू.-5 और एक्स. एच. जैसे गवाहों के बयानों के अवलोकन पर। पी-1 से पी-12 तक, यह स्पष्ट है कि अपराधी सिपाही की सही जन्म तिथि 21.04.1974 थी। जब अपराधी सिपाही ने सिपाही के पद पर भर्ती के लिए आवेदन जमा किया, तो उस समय उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, इसलिए कम आयु के कारण उसके आवेदन की अस्वीकृति की आशंका के कारण, अपराधी सिपाही ने अपनी जन्म तिथि को 21.04.1974 से 21.04.1972 के रूप में बदल दिया है, इसलिए आरोप संख्या 1 साबित होता है।

अपराधी सिपाही ने भी 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिसकी मार्कशीट एक्सएच है। पी-4, जिसमें उनकी जन्म तिथि 21.04.1974 के रूप में उल्लिखित है।” जहाँ तक आरोप-2 का संबंध है, यह केवल देखा गया कि आपराधिक मामले में चालान का नेतृत्व जांच रिपोर्ट की तारीख 28.02.2004 पर किया गया था और मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था।

20. 'निष्कर्ष' शीर्षक के तहत जांच रिपोर्ट के ऑपरेटिव भाग में, 8 वीं कक्षा की मार्कशीट (जो कॉन्स्टेबल राज सिंह द्वारा आरोप पत्र के साथ भेजे गए संलग्न दस्तावेजों का हिस्सा था) या बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित Exh.D-3 [मूल 8 वीं कक्षा की मार्कशीट] का कोई संदर्भ नहीं है। राज सिंह पीडब्लू-5 817 के बयान का भी कोई संदर्भ नहीं है।

राम लाल वी. स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ओआरएस।

जांच में, जिन्होंने स्वीकार किया था कि 8 वीं कक्षा की अंकतालिका में कोई बदलाव नहीं किया गया था। प्रदर्शनी के चार्ट में जगदीश चंद का पत्र (Ex.P1); जगदीश चंद द्वारा जारी 8 वीं कक्षा की डुप्लिकेट मार्कशीट (Ex.P2); श्रवण लाल (पूर्व-P3) का विवरण; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की 10 वीं कक्षा की मार्कशीट (Ex.P4); सर्कल ऑफिसर, किशनगढ़ (पूर्व-ID1) द्वारा प्रारंभिक जांच दिनांकित है। पी5); एफ. आई. आर. नं. 183/2000, (Ex.P6); कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए राम लाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन (Ex.P-7); नियुक्ति पत्र दिनांक 08.11.1991 (ExP-8); रामलाल के नेतृत्व में सत्यापन पत्र (Ex.P9); नियुक्ति आदेश दिनांक 16.12.1991, (Ex-P-10); सरकारी स्कूल तिलोनिया का पत्र, Ex.P-11; और आरोप पत्र दिनांक 24.04.2003, Ex.P-12।

21. यह बहुत स्पष्ट है कि प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य, पीडब्लू-5/राज सिंह का बयान; अपीलार्थी की 8 वीं कक्षा की अंकपत्रिका [आरोप पत्र के साथ संलग्न] और मूल अंकपत्र को स्वतंत्र रूप से पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। रक्षा द्वारा डी3 को चर्चा और विचार में पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। अभिलेख पर आए महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य की अनदेखी करके आरोपों के प्रमाण के बारे में निष्कर्ष निकाला गया है। पीडब्लू-5 राज सिंह का साक्ष्य और आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में संलग्न अंकपत्र और पूर्व के रूप में चिह्नित मूल अंकपत्र। डी-3, ऐसी सामग्री थी जिसका चार्ज पर सीधा असर होता था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने केवल जांच रिपोर्ट में तर्क को दोहराया है। समान रूप से अपीलीय प्राधिकरण के कार्य भी ऐसे ही हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि संबंधित सामग्री की अनदेखी करने के बाद अनुशासनात्मक अधिकारियों के निर्णय पर पहुंचा जाता है तो न्यायिक समीक्षा में अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। यह केवल इस हद तक खुद को संतुष्ट करने के लिए है कि हमने यह देखने के लिए सामग्री की जांच की है कि रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड किया गया था। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही दूषित हो गई है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। 22. इस परिदृश्य में, हम अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि आवेदन पत्र में पुनर्लेखन केवल अनजाने में हुई त्रुटि के सुधार के कारण था। जब तक मूल 8 वीं कक्षा की मार्कशीट में उसकी जन्म तिथि को 21.04.1972 के रूप में दर्शाया गया है और उस दस्तावेज में कोई सुधार या हेरफेर नहीं है, तब तक अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है।

आपराधिक कार्यवाही में बरी होने का प्रभाव-प्रश्न संख्या **2:**

23. उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, यदि हम आपराधिक कार्यवाही की जांच करते हैं तो निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति सामने आती है। वही गवाह, जो थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

विभागीय जाँच में जाँच की गई आपराधिक मुकदमे में जाँच की गई। जगदीश चंद्र, भवानी सिंह, श्रवण लाल, राज सिंह और करण शर्मा से आपराधिक मुकदमे में क्रमशः पीडब्लू2, पीडब्लू3, पीडब्लू6, पीडब्लू9 और पीडब्लू13 के रूप में पूछताछ की गई। इनके अलावा आठ अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई। आपराधिक मामले में आरोप की गंभीरता यह थी कि अपीलार्थी ने अपनी अंकपत्रिका के साथ भर्ती के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था और उसने अपनी जन्म तिथि में परिवर्तन करके 21.04.1974 के स्थान पर 24.04.1972 के रूप में पुनः आवेदन किया था और सिपाही के पद पर भर्ती प्राप्त की थी। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत दोषी ठहराया, अपील न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज किए:

“...मुख्य रूप से वर्तमान मामला इस आशय के दस्तावेजों पर आधारित था कि क्या आरोपी की जन्म तिथि 21.04.1972 या 21.04.1974 है। एक्सएच। पी-3 मूल मार्कशीट है, जिसमें अभियुक्त की जन्म तिथि 21.04.1972 के रूप में दिखाई गई है और अभियोजन पक्ष की ओर से जांचे गए गवाहों द्वारा भी यह साबित किया गया है। 21.04.1974 की जन्म तिथि के संबंध में न्यायालय के समक्ष जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वे या तो प्राचार्य के पत्र हैं या डुप्लिकेट टी. सी. या मार्कशीट हैं। न तो अभियोजन पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय के कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि जब अभियुक्त का प्रवेश पत्र दाखिल किया गया था, तो उसमें अभियुक्त द्वारा किस जन्म तिथि का उल्लेख किया गया था, स्कूल के रोल रजिस्टर में जन्म तिथि क्या थी, माध्यमिक परीक्षा प्रपत्र में अभियुक्त द्वारा किस जन्म तिथि का उल्लेख किया गया था, और न ही संबंधित गवाहों से मूल अभिलेख लाने के बाद, वे साक्ष्य में साबित हुए थे। इन परिस्थितियों में, यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है कि अभियुक्त की जन्म तिथि 21.04.1974 थी, और अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एल. डी. द्वारा दी गई दोषसिद्धि। अधीनस्थ न्यायालय केवल मौखिक साक्ष्यों और पत्रों या डुप्लिकेट दस्तावेजों के आधार पर न्यायसंगत और उचित नहीं है। अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायसंगत है।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त विचार के आधार पर, अपीलार्थी/अभियुक्त के नेतृत्व में वर्तमान अपील को अनुमति दी जा सकती है।” [जोर दिया गया] 819

राम लाल वी. स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ओआरएस।

24. ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलीय न्यायाधीश ने दस्तावेज में इसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया है। पी-3-8 वीं कक्षा की मूल अंकपत्रिका, जन्म तिथि स्पष्ट रूप से 21.04.1972 के रूप में दिखाई गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज या तो अक्षर या डुप्लिकेट अंकपत्र थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायाधीश का कहना है कि यह संदिग्ध हो जाता है कि जन्म

तिथि 21.04.1974 थी या नहीं और अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार था। हालाँकि, हमें जो देखना है वह निर्णय का सार है। पूरे फैसले को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद और यह देखने के बाद कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, बरी कर दिया गया था [एस. समुथिरम देखें]।

(सुप्रा)।]

25. निर्णयों में उपयोग की जाने वाली "संदेह का लाभ" और "सम्मानपूर्वक बरी" जैसी अभिव्यक्तियों को जादू के मंत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कानून की अदालत केवल इस तरह की शब्दावली के उपयोग से प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान मामले में, अपीलीय न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि एक्सएच। पी-3, मूल अंकपत्र में जन्म तिथि 21.04.1972 होती है और यह अभियोजन पक्ष की ओर से जांचे गए गवाहों द्वारा भी साबित किया गया है। यह निष्कर्ष कि आपराधिक कार्यवाही में बरी होना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद था और अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा, निर्णय को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में न्यायालय निर्णय के सार की जांच करने के लिए बाध्य है और उपयोग की गई अभिव्यक्ति के रूप में नहीं जाता है।

26. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आपराधिक मामले में अपीलीय न्यायाधीश के आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप उचित नहीं था, "साबित नहीं हुआ"-वास्तव में आरोप अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा भी "गलत" साबित हुआ। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, एक तथ्य को "अस्वीकृत" कहा जाता है, जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह मानता है कि इसका अस्तित्व नहीं है या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि इसका अस्तित्व नहीं है। एक तथ्य को "सिद्ध नहीं" कहा जाता है जब वह न तो "सिद्ध" होता है और न ही "सिद्ध" होता है।

"अस्वीकृत" [विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 3 एस. सी. सी. 190 देखें]।

27. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही और उस पर पारित आदेशों को कायम नहीं रहने दिया जा सकता है। आरोप न केवल समान थे बल्कि समान थे और सबूत, गवाह और परिस्थितियाँ सभी समान थीं। यह एक मामला है

820

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जहाँ हम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को रद्द करते हैं क्योंकि उन्हें खड़े होने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा। यह मामला उस स्थिति के समान है जो उत्पन्न हुई थी

जी. एम. टैंक (ऊपर)।

28. उपरोक्त के अलावा, एक अन्य पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्क्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट में अपीलार्थी के 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने और 10 वीं कक्षा की मार्कशीट को एक्सएच के रूप में प्रदर्शित करने का संदर्भ दिया गया है। पी-4 जन्म तिथि को 24.07.1974 के रूप में संदर्भित करता है। जगदीश चंद्र-पीडब्लू1 (विभागीय जांच में) ने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि अपीलकर्ता नियमित रूप से 10 वीं कक्षा से अनुपस्थित था, इसलिए उसका नाम रद्द कर दिया गया और वह 10 वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाया। अपीलार्थी ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष यह कथन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि पूछताछ कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत राम लाल का 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र किसी अन्य राम लाल का है।

29. इस मुद्दे को हमें और रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विभाग का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने 10 वीं कक्षा की अंकपत्रिका के आधार पर रोजगार की मांग की थी। यह उनका सकारात्मक मामला है कि अपीलार्थी ने अपनी 8 वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर रोजगार की मांग की थी। श्रवण लाल-पीडब्लू-4 ने विभागीय जांच में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से प्राप्त 10 वीं कक्षा की मार्कशीट भी प्रस्तुत की थी। जिरह में, पूछे जाने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलार्थी की भर्ती 8 वीं कक्षा की मार्कशीट के आधार पर की गई थी, और उन्होंने स्वीकार किया कि 8 वीं कक्षा की मार्कशीट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि समाप्ति का आदेश दिनांक 31.03.2004; अपीलीय प्राधिकरण का आदेश दिनांक 08.10.2004; आदेश दिनांक 29.03.2008 और 25.06.2008 क्रमशः दंड पर पुनर्विचार और समीक्षा करने से इनकार करते हुए, सभी अवैध और असमर्थनीय हैं।

31. तदनुसार, हम डी. बी. विशेष अपील (रिट) No.484/2011 दिनांक 05.09.2018 के फैसले को दरकिनार करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को वरिष्ठता, काल्पनिक पदोन्नति, वेतन की राशि और अन्य सभी लाभों सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाएगा। जहाँ तक बैकवेज का संबंध है, हम अपीलार्थी को बैकवेज का 50 प्रतिशत देने के लिए इच्छुक हैं। इन निर्देशों का पालन आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

32. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन